



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1975/आश्विन 4, 1997

Ns. 387] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975/ASVINA 4, 1997

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th September 1975

S.O. 541(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 455(E)/18FB/IDRA/73, dated the 31st August, 1973, (hereinafter referred to as the said order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the Industrial undertaking known as Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industry and Civil Supplies by Order No. S.O. 700(E)/18FB/IDRA/74 dated the 6th December, 1974, extended the duration of the said Order upto the 30th August, 1975;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th day of August, 1976.

[No. F. 1/92/71-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)**

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

का० आ० 541(अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/75.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 455 (अ०)/18/चख/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 31 अगस्त, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंचाट, या अन्य लिखित का, जिसमें मेसर्स कार्टर पूलर एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लाभ हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार ने उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 700 (अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/74, तारीख 6 दिसम्बर, 1974 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 अगस्त, 1975 तक बढ़ा दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 30 अगस्त, 1976 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 1/92/71—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।